23-24 जनवरी को शिलोंग, मेघालय में आयोजित 69वीं पूर्वोत्तर परिषद की सभा में असम के माननीय राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी का भाषण

आदरणीय गृहमंत्री, भारत सरकार तथा उत्तर पूर्व परिषद के
अध्यक्ष श्री अमित शाह जी,

उत्तर पूर्व राज्यों के माननीय राज्यपाल

उत्तर पूर्व राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री

माननीय डोनर मंत्री

उत्तर पूर्व परिषद के माननीय सदस्य

उत्तर पूर्व राज्यों के माननीय मंत्रीगण

डोनर सचिव

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के सचिवगण

उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्य सचिवगण

उत्तर पूर्व परिषद के सचिव

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार तथा अन्य प्रतिष्ठान

देवियों एवं सज्जनों,

यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का पल है कि मुझे इस सभा में गणमान्य नेताओं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों तथा सबसे बड़ी बात तो यह है

कि 69वीं सभा के अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री **श्री अमित शाह** जी के समक्ष अपने विचार को रखने का मौका मिला है।

भारत, कोविड-19 महामारी जैसी विषम परिस्थिति में भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम में भी हम इस कोविड - 19 महामारी जैसी विषम परिस्थिति को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एवं श्री अमित शाह जी के अनवरत सहयोग से सफलता पूर्वक निपटने में कामयाब होते हुए विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

पूवोत्तर परिषद की 69वीं सभा की मौजूदा परिदृश्य में काफी अहमियत बढ़ जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों को अवसर मिल जाता है कि हम एक सामान्य मंच पर एकत्र हो कर अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर सकें तथा रोडमैप तैयार करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति सुनिश्चित कर सकें। इस अवसर पर हम जरूरी क्षेत्र के विकास, राज्य के लिए विशिष्ट तौर पर जरूरी आवश्यकताओं तथा परियोजनाओं, विकास पैकेजों पर चर्चा करेंगे तथा विकास केंद्रित रणनीतियों, सुदीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारण तथा कार्यान्वयन आदि संबंधी नीतियों को अमलीजामा पहनाएंगे।

मैं आशा करता हूं कि हम माननीय गृहमंत्री एवं एनईसी के अध्यक्ष की उपस्थिति का लाभ उठाने में कामयाब होंगे तथा पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रतिबिंबित करने में सफल होंगे।

असम तथा खासकर गुवाहाटी की स्थिति रणनीतिक रूप से पूर्वोत्तर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गुवाहाटी - पूर्वोत्तर (एनई) का प्रवेशद्वार है तथा असम से पूर्वोत्तर राज्यों के किसी जगह सड़क मार्ग से या वायुमार्ग से हम सुगमता से पहुंच सकते हैं। असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का लाभ पड़ोसी राज्यों को मिल रहा है। जिसमें खासकर सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य मार्ग), स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान, भंडारणगृह, प्रशीतन गृह आदि शामिल हैं। इसलिए मैं पूर्वोत्तर परिषद से आग्रह करता हूं कि वह महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान कर ऐसी बड़ी परियोजनाओं को अंजाम दे, जिसका असम में बहुआयामी प्रभाव हो।

कोविड-19 महामारी के चलते हम कठिन हालातों से गुजर रहे हैं। इसने न सिर्फ देश को, अपितु समूचे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। नए जॉब बहुत सीमित हैं। बहुत से लोग अपने काम-रोजगार गंवा बैठे हैं। व्यवसाय कोविड-19 से पहले की स्थिति में नहीं लौट पाए हैं। मैं इस सभा में एक बार फिर आग्रह करता हूं कि रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएं ताकि युवाओं को रोजगार खासकर क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

दूसरी तरफ कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की मांग काफी बढ़ी है। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ती मांग तथा स्वास्थ्य कर्मियों, जैसे कि चिकित्सक, नर्स, चिकित्साकर्मी, लेब टेक्नीशियन आदि की कमी के मद्देनजर, मैं एनईसी से फिर आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में चिकित्सा संरचना को संवर्धित करने पर विशेष बल दिया जाए और अधिक पेरामेडिकल संस्थान, नर्सिंग संस्थान, विशिष्ट तरह की प्रयोगशालाएं सुस्थापित की जाएं। यहां से प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्स न सिर्फ पूर्वोत्तर में मानव संसाधन की कमी को पूरी करेंगे, अपितु अन्य राज्यों में होने वाली कमी को भी पूरा करेंगे।

कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत से लोगों ने अपने व्यवसाय, शिक्षा एवं अन्य सेवाओं को अपने-अपने घरों से निष्पादित किया। इसके लिए अबाध इंटरनेट सेवा की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई। यद्यपि इस दौरान यह देखने में आया कि असम के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट की सेवाएं अच्छी नहीं रहीं। इस क्षेत्र में इंटरनेट नेटवर्क में सुधार के लिए बांग्लादेश के काक्स बाजार से होकर पूर्वोत्तर राज्यों में आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को प्रस्तावित किया गया है। इसलिए मै फिर से आग्रह करता हूँ कि इस मामले पर गौर करें तथा इसे हल करें ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर एवं तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी संभव हो सके।

दूसरी ओर, पूर्वोत्तर समेत पूरे देश के लिए डिजिटल ईकॉनोमी और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिल रहा है यद्यपि विशेष रुप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस पर और अधिक निवेश की आवश्यकता है।

असम में हाल के वर्षों में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2018-19 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद रु. 36,662 करोड़ रहा , जो राज्य के जीडीपी का 15.8 प्रतिशत रहा। यद्यपि राज्य के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में लगे लोगों का प्रतिशत अभी भी लगभग 80 प्रतिशत बना हुआ है। यह क्षेत्रवार जो वृद्धि बनी हुई है यह खासकर सुदृढ़ मशीनीकरण, सुनिश्चित सिंचाई, रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग, उच्च उत्पादन के बीजों (एचवाईवी) का उपयोग तथा मृदा शोधन रहा है। कृषि के अलावा राज्य में बागवानी, फूलों की खेती, मसालों तथा जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। मैं एनईसी से आग्रह करता हूं कि वह इस क्षेत्र को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए।

असम बांस के उत्पादन में सुसंपन्न है और यहां यह काफी मात्रा में पाया जाता है। यह एनईसी के लिए प्राथमिक क्षेत्र में से एक है। बांस के महत्व को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने हाल ही में अपनी नीतियों में संशोधन किया है। अब बांस को वनोत्पाद की श्रेणी से हटाकर कृषि उत्पाद के रूप में घोषित
किया है। इस नीतिगत संशोधन से इसका उत्पादन और सहज होगा और बांस की कच्चे माल के रूप में खरीद बढ़ेगी। बांस और बेंत क्षेत्र का विकास पूरे पूर्वोत्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

असम के छोटे चाय बागानों / उत्पादकों द्वारा बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2018 के दौरान राज्य की 44 प्रतिशत चाय छोटे उत्पादकों द्वारा पैदा की गई। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग कार्य करते हैं और इस क्षेत्र में रोजगार की और अधिक संभावनाएं तथा आर्थिक अवसर विद्यमान हैं। मैं एनईसी से आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास की ओर और अधिक ध्यान दे।

राज्य में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं विद्यमान हैं। वर्ष 2019 में राज्य में क्रमश: 945.92 मिलियन ली. दूध, 5042 हजार टन मांस तथा 5015 लाख अंडों का उत्पादन किया गया। लेकिन यह उत्पादन अभी भी नाकाफी है। इन सामानों की पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी

अधिक मांग है। इसी तरह से हमारे पड़ोसी देशों में भी इनकी काफी मांग है। इन जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर, मैं एनईसी से आग्रह करता हूं कि वह दुग्ध, मांस तथा अंडों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ प्रसंस्करण इकाइयों, फीड मिल्स, स्वास्थ्यकर एवं स्वच्छ मांस वध गृहों आदि के निर्माण को सुनिश्चित करे।

मछली पालन एक अन्य क्षेत्र है जहां काफी संभावनाएं हैं। राज्य के अधिकांश क्षेत्र समतल (पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के विपरीत) हैं तथा यहां प्राकृतिक जलाशय हैं जो मछली के उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है। राज्य में मांग और आपूर्ति के बीच काफी अंतर है तथा वर्ष 2019-20 के बीच अन्य राज्यों से 20,073 टन मछली आयातित की गई। राज्य में कमी की खाई को भरने के लिए असम सरकार ने मुख्यमंत्री समग्र ग्राम उन्नयन योजना के अंतर्गत कई योजनाएं चला रखी है। मैं एनईसी से आग्रह करता हूं कि क्षेत्र में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र की ओर भी विशेष ध्यान दे।

असम में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, खासकर वन्यजीवों, पक्षियों, प्राकृतिक एवं सुरम्य सुंदरता, नदियों, झरनों आदि के पर्यटन गंतव्यों के विकास के माध्यम से पूर्वोत्तर के पड़ोसी राज्यों के विकास के साथ हम असम में पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ा सकते हैं। इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर विद्यमान हैं तथा मैं एनईसी से आग्रह करता हूं कि वह राज्य के साथ-साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पर्यटन संरचना, होम स्टे सुविधाओं, ईको-टूरिज्म, टी टूरिज्म आदि के संवर्द्धन के लिए और राशि उपलब्ध कराए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य, पूर्वोत्तर के आठों राज्यों में सबसे बड़ा है। यहां 3.5 करोड़ लोग निवास करते हैं। मेरे राज्य को बार-बार बाढ़ एवं भू-स्खलन की समस्या से रू-ब-रू होना पड़ता है। आज तक हमने 4.27 लाख हेक्टेयर भूमि नदियों के कटाव के कारण गंवा दी हैं तथा करीब 1.25 लाख लोग बेघर हो गए हैं। एनईसी के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय से यह मेरा विनम्र आग्रह है कि वह बाढ़ एवं भू-स्खलन जैसी विभीषिका से बचाव के लिए राज्य को और अधिक धन उपलब्ध कराएं।

जैसा कि ज्ञातव्य है कि हम अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से रेल, सड़क या हवाई मार्गों से एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का लाभ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी मिलता है। मैं एनईसी से आग्रह करता हूं कि राज्य की मदद की राशि को और बढ़ाए, खासकर असम के लिए आवंटित राशि जो कि वर्ष 2020-21 में मात्र 52 करोड़ रुपये है, मैं उस राशि को बढ़ाकर प्रति वर्ष रु. 300-400 करोड़ करने का आग्रह करता हूँ।

मैं समय के अभाव में असम की चंद समस्याओं से आपको अवगत करा सका। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ आज और कल होने वाली बैठकों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श होंगे। मुझे आशा है कि आज की सभा से हमारे अंदर नए विचार पल्लवित होंगे तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेज एवं टिकाऊ विकास में बेहतर पहल का शुभारंभ होगा। मैं पूर्वोत्तर परिषद से आग्रह करता हूं कि वह क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करे ताकि इस क्षेत्र के लोग भारत के विकसित राज्यों की तरह विकास का अनुभव कर सकें।

कोविड महामारी की परिस्थिति और इससे बहुत पहले, जब एक्ट-ईस्ट पॉलिसी की शुरुवात हुई थी तभी से भारत की ओर से पूर्वोत्तर से सटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर सम्बंध बनाए रखने हेतु पहल की जा रही है। इस पॉलिसी के तहत बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) और बांग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका और थाईलैंड इकॉनोमिक को-ओपारेशन (BIMST-EC) के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई देशो के साथ पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक सहभागिता बढ़ने पर इस क्षेत्र का सच्चे अर्थो मे विकास और सहभागिता मजबूत होगी। मै समझता हूँ, इस विकास यात्रा मे एनईसी एक सेतु का काम कर सकती है। एनईसी के वेब पॉर्टल के जरिये पूर्वोत्तर के सभी राज्य अपने विकास की गति और सभी आकड़े इकट्ठे कर एक मंच पर साझा करने में सक्षम हो सकेंगे। मुझे खुशी है की पूर्वोत्तर का आत्मिक संबंध देश के अन्य राज्यों के साथ दिन-ब-दिन बेहतर हो रहा है।

अंतत: मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा उत्तर पूर्व परिषद को अपना धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इस बात का अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचारों एवं उद्विग्नताओं को साझा कर सकूं।

जय हिन्द।